बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 247

प्रतिगामी होगा परिवार बढ़ाना

भारत इस तथ्य से गौरवान्वित हो सकता है कि देश की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है और वह 1965 के प्रति महिला पांच बच्चों से कम होकर 2022 में 2.01 पर आ गई है। आपातकाल के दौर के 18 महीनों को छोड़ दिया जाए तो यह कमी नागरिक अधिकारों का किसी तरह दुरुपयोग किए बिना हासिल की गई है। ध्यान रहे चीन में यह दर कम करने के लिए 36 वर्षों तक एक बच्चा पैदा करने की नीति लागू की गई थी। कुल प्रजनन दर में कमी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए पूरी तरह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह दर 2.1 की प्रतिस्थापन या रीप्लेसमेंट दर से कम हो गई है। रीप्लेसमेंट दर वह होती है जितने बच्चे हर महिला के हों तो देश में बुजुर्गों और युवाओं की संख्या स्थिर बनी रहती है। लैंसेट के एक अध्ययन पर यकीन किया जाए तो 2050 तक देश की कुल प्रजनन दर 1.29 हो जाएगी। यानी भारत अमीर होने के पहले ही उम्रदराज हो सकता है। देश की जनांकिकी के इस भविष्य से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति को मजबूत बनाया जा सकता है, श्रम शक्ति को सही ढंग से प्रशिक्षित किया जा सकता है और बीमा योजनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में इसका उपाय तीन संतानों के रूप में दिया है। इसे अपनाने के विषय में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

भागवत ने नागपुर में एक सभा में इस बात पर जोर दिया जबकि महज दो साल पहले वह जनसंख्या नियंत्रण का आह्वान करते नजर आ रहे थे। तब उनका संकेत हिंदुओं और मुस्लिमों की कुल प्रजनन दर के बीच असमानता की ओर था। अब, जबकि आबादी की वृद्धि दर में कमी आ रही है और भारत में जनांकिकीय ठहराव आने की संभावना बन गई है तब उन्हें देश के समक्ष एक खतरा नजर आ रहा है। जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देना वृद्धि को गति प्रदान करने की दृष्टि से सरल प्रतीत हो सकता है। कुछ स्कैंडिनेवियन (डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि) और यूरोपीय देश दशकों से आबादी में कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। वे परिवारों को चाइल्ड केयर प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं। परंतु इन देशों ने सामाजिक-आर्थिक प्रगति का एक स्तर और प्रशासनिक क्षमता हासिल कर ली है और वह भी बिना सामाजिक रूप से प्रतिगामी हुए (उदाहरण के लिए समान पितृत्व अवकाश)। भारत जैसे असमान देश में जहां कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति असमान और गैर किफायती है, तीन बच्चे पैदा करने का नियम नुकसानदेह हो सकता है। आबादी में बेतहाशा वृद्धि उन सामाजिक लाभों को नुकसान पहुंचाएगी जो देश ने आजादी के बाद हासिल किए हैं। उदाहरण के लिए ऐसी नीति महिला अधिकारों के खिलाफ है क्योंकि बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने का पूरा बोझ महिलाओं पर पड़ता है। इससे एक ही झटके में वे सभी लाभ खत्म हो जाएंगे जो महिलाओं ने उच्च शिक्षा, कार्यालयों और दुकानों आदि में जाकर हासिल किए हैं। गरीब और रुढ़िवादी परिवारों से आने वाली महिलाओं को ऐसे मानकों का नुकसान उठाना पड़ेगा।

देश में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 37 फीसदी है और यह लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। महिलाओं पर बोझ डालने से हालात में कोई सुधार होने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वालों के लिए दो बच्चों की सीमा समाप्त कर दी है और सरकार बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। तेलंगाना भी उसका अनुसरण कर सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता जायज है कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके प्रगतिशील कदम वित्त आयोग के आवंटन और संसदीय सीटों के परिसीमन में उनके खिलाफ जाएंगे। ये आशंकाएं पूरी तरह गलत नहीं हैं और इसे नीतिगत स्तर पर हल करने की आवश्यकता है ताकि इन राज्यों का जननांकिकीय लाभ उत्तर भारत के गरीब और अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए आदर्श बन सके। बड़े परिवारों को प्रोत्साहन देना प्रतिगामी कदम होगा। इसके बजाय देश भर में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विनय सिन्हा

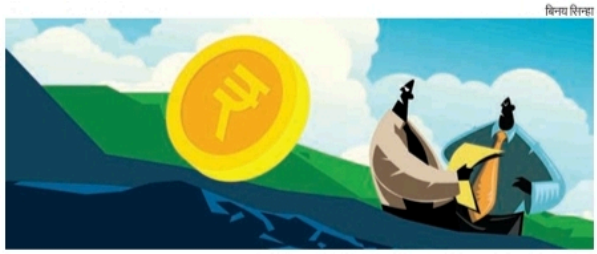

पूंजी प्रवाह पर क्या हो सही प्रतिक्रिया

रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में जो हस्तक्षेप किया है वह आवश्यक था। परंतु अब उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये में आगे और अधिमूल्यन न हो। बता रहे हैं जनक राज

भारतीय रुपया सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में उस समय दबाव में आ गया जब विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय पूंजी बाजार में विशुद्ध बिकवाली आरंभ कर दी। इसके परिणामस्वरूप पूंजी बाहर जाने लगी। बहरहाल, व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में दखल दिया जिससे कुछ हलकों में यह चिंता भी उत्पन्न हुई कि क्या यह सही रणनीति है?

एफआईआई ने 25 सितंबर से भारतीय बाजार से पूंजी निकालनी शुरू की। इससे एक दिन पहले ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने मौद्रिक प्रोत्साहन घोषित किया था। इसके तुरंत बाद चीन में राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। चूंकि चीन में शेयरों का मूल्यांकन सस्ता था और प्रोत्साहन ने शेयर कीमतों में इजाफे की संभावना पैदा कर दी थी इसलिए एफआईआई ने भारत से पैसा निकालकर चीन में निवेश करना आरंभ कर दिया।

इन निवेशकों के बाहर जाने की दूसरी प्रमुख वजह थी भारतीय कंपनियों की ओर से दूसरी तिमाही के निराश करने वाले परिणाम। खासतौर पर कुछ जानी-पहचानी दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियां। इससे संकेत निकला की देश में खपत कमजोर पड़ रही है। इससे भारतीय शेयरों का मूल्यांकन और अधिक महंगा हो गया और एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में बिक्री जारी रखी।पोर्टफोलियो निवेशकों के बाहर जाने की तीसरी वजह रही छह नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का नतीजा। यह मानते हुए कि नए प्रशासन की नीतियां मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाली होंगी तथा अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व शायद फेड फंड में अपेक्षित कटौती नहीं कर सकेगा, डॉलर सूचकांक (छह अन्य प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की मजबूती आंकने वाला) जो पहले ही 103.4 के उच्च स्तर पर था, वह चुनाव परिणामों के दिन बढ़कर 105.1 पर पहुंच गया। इसमें लगातार मजबूती आती रही और 26 नवंबर को यह 107 हो गया। हालांकि अगले दिन यह पुनः कम होकर 106.1 रह गया। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत है और एफआईआई जोखिम से मुक्त हैं। मजबूत डॉलर आमतौर पर भारत समेत उभरते बाजारों के लिए नकारात्मक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चलते डेट और इक्विटी दोनों बाजारों से पूंजी बाहर जाती है।

27 सितंबर से 25 नवंबर के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में नॉमिनल स्तर पर 0.7 फीसदी अवमूल्यन देखने को मिला। बहरहाल, यह अवमूल्यन समान अवधि में अधिकांश उभरते और विकसित देशों की मुद्राओं में हुए अवमूल्यन की तुलना में काफी कम था। उदाहरण के लिए रूसी रूबल में इस अवधि में 10.1 फीसदी की गिरावट आई। जापानी येन, मलेशियन रिंगिट, थाई भाट, ब्राजीलियन रियल, दक्षिण कोरियाई वॉन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और फिलीपींस की मुद्रा पेसो में 5 से 7.6 फीसदी गिरावट देखी गई। इंडोनेशियाई रुपिया, मैक्सिकन पेसो, अर्जेंटिना के पेसो और चीन की मुद्रा युआन में 3.2 से 4.8 फीसदी के बीच गिरावट देखने को मिली। तुर्की की मुद्रा लीरा में 1.3 फीसदी गिरावट आई।

25 सितंबर से 25 नवंबर के बीच करीब 14.3 अरब डॉलर मूल्य का निवेश एफआईआई ने निकाला। इससे विदेशी मुद्रा बाजार के लिए अजीब हालात तैयार हो सकते थे। ऐसे में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित रखने की अपनी नीति के तहत रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में दखल दिया। यही वजह है कि उसके भंडार में 47 अरब डॉलर की कमी आई और वह 27 सितंबर 2024 के 705 अरब डॉलर से कम होकर 15 नवंबर 2024 को 658 अरब डॉलर रह गया।

विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी कुछ हद तक मूल्यांकन प्रभाव के कारण थी क्योंकि अन्य आरक्षित मुद्राओं की कीमत भी डॉलर की तुलना में कम हो रही थी। वहीं 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल के 25 सितंबर के 3.79 फीसदी से बढ़कर 25 नवंबर को 4.27 फीसदी होने के बाद बॉन्ड कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बहरहाल अक्टूबर-नवंबर में विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के बावजूद रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार कैलेंडर वर्ष के आधार पर 35 अरब डॉलर अधिक रहा। वित्तीय वर्ष के आधार पर भी 15 नवंबर 2024 तक यह 12 अरब डॉलर ज्यादा था।

पूंजी की वापसी के तमाम हालिया प्रकरणों में रुपये का अवमूल्यन तेजी से हुआ था। उत्तर-अटलांटिक वित्तीय संकट (अगस्त 2008 से मार्च 2009) के दौरान इसमें 16 फीसदी, 2013 में टैपर टैंट्रम (23 मई से 30 अगस्त) के दौरान 15.4 फीसदी, चीन में मंदी और युआन के अवमूल्यन (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016) के दौरान 8.7 फीसदी, कोविड महामारी के दौरान 5.0 फीसदी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न भूराजनैतिक चिंताओं के बीच इसमें 6.5 फीसदी की गिरावट आई। ऐसे में अगर रिजर्व बैंक हस्तक्षेप नहीं करता तो 14 अरब डॉलर मूल्य की राशि का बाहर जाना विदेशी मुद्रा बाजार में विसंगति पैदा कर सकता था और वास्तविक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता था।

भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था और लचीली दर वाले देश में विदेशी मुद्रा भंडार प्रमुख रूप से सावधानी के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसे रेखांकित करने वाला तर्क यह है कि विदेशी मुद्रा बाजार में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर जोखिम कम हो। अगर विपरीत हालात बन ही जाते हैं तो केंद्रीय बैंक को इन मुद्रा भंडारों का इस्तेमाल करके विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर रखना चाहिए।

वास्तव में विदेशी मुद्रा भंडार तैयार करने के तमाम उद्देश्यों में सबसे प्रमुख और सबसे कम विवादास्पद उद्देश्य है पूंजी प्रवाह में तत्काल रुकावट अथवा पूंजी के अचानक बहिर्गमन को रोकना ताकि वास्तविक अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा बाजार में विसंगतिपूर्ण परिस्थितियों के दुष्प्रभाव को रोका जा सके।

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि मुद्रा के बाहर जाने के बाद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी उसके जून 2024 तक के बाहरी कर्ज दायित्वों में से 96 फीसदी की भरपाई करने में सक्षम है। यह मोटे तौर पर किसी देश के पूंजी खाते की संवेदनशीलता का आकलन करने वाला उपाय है। इससे संकेत मिलता है कि यह आने वाले साल के कर्ज संबंधी दायित्वों को निभाने के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए।

21 नवंबर को 84.49 रुपये प्रति डॉलर के साथ रुपया अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया था हालांकि 40 मुद्राओं की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर अक्टूबर में 107.2 पर थी। यह बताता है कि रुपया अधिमूल्यित था। अक्टूबर में इसमें 1.8 फीसदी का इजाफा हुआ और मार्च 2022 की तुलना में 2.7 फीसदी का। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर निर्यात प्रतिस्पर्धा के आकलन के लिए उपयुक्त है, खासतौर पर वस्तु निर्यात के मामले में। अब जबकि पूंजी के और बाहर जाने का जोखिम कम हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाजार दोनों स्थिर हो चुके हैं तथा दो माह तक लगातार बिकवाली के बाद 22-27 नवंबर के बीच एफआईआई ने भी विशुद्ध खरीदारी की तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के स्तर पर रुपये में और अधिमूल्यन न आए।

विकसित भारत के लिए बदला दृष्टिकोण

विकसित भारत एक ऐसा सुखद नागरिक-आधारित दृष्टिकोण है, जो उम्मीद जगाता है कि एक दिन हम जरूर अपने लक्ष्य को अपने दम पर हासिल करने में कामयाब होंगे। यह वैश्विक रैंकिंग प्रतिस्पर्धा से अलग हट कर वह विमर्श है, जो पिछले कुछ वर्षों से सरकार और उद्योग जगत की नीतियों में स्पष्ट झलक रहा है।

इसका मकसद अपने सभी नागरिकों को बेहतर और उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक संपन्नता हासिल करना है (यद्यपि कई मीडिया रिपोर्ट इस तथ्य को समझने में नाकाम रहीं और वे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं विश्व रैंकिंग में सुधार वाले उसी पुराने ढर्रे को विकसित भारत के पैमाने के तौर देखती रहीं)। यदि समग्र रूप में देखें तो अब चर्चा एक छोटे वर्ग की तरक्की के दम पर विश्व रैंकिंग में स्थान बनाने के बजाय सभी भारतीयों को कुशल एवं योग्य बनाकर उनकी प्रतिभा को देश हित में इस्तेमाल करने की तरफ मुड़ गई है।

निःसंदेह हमारी विश्व रैंकिंग एक बड़ी उपलब्धि है, जो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन इसी से संतुष्ट होकर बैठ जाना और यह कहना कि पुरानी परिपाटी पर चलने के अलावा अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है तथा कहावत के अनुरूप इस दृष्टिकोण को नकारना कि 'सोने से पहले हमें अभी भी बहुत कुछ करना है' बहुत बड़ी भूल होगी।

हालिया वित्तीय तिमाही के समाप्त होने के बाद कई कारोबारी सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें 'ओआर की निरंकुशता' (प्रबंधन गुरु सीके प्रह्लाद द्वारा गढ़ा गया वाक्यांश) पर काफी चर्चा हुई। एक वर्ग का मानना है कि दूसरों के इस तथ्य कि 'बहुत अधिक संख्या में जीडीपी डॉलर एकत्र करके और इसी आधार पर आगे बढ़ने से हमारा कितना विकास होगा और कौन सी रैंक हासिल होगी' के बजाय अपनी क्षमता को पहचान कर सही दिशा में काम करना एकमात्र सत्य है।

इसके समर्थकों का मानना है कि यह दूसरे खंड से मेल नहीं खाता है, जो यह इंगित करने में 'अव्यावहारिक' है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, क्योंकि अधिकांश लाभ अभी भी आय पिरामिड के शीर्ष तक ही सीमित है - एक वास्तविकता जो शेयर बाजार में भागीदारी में वृद्धि के बावजूद सच है।

रमा बीजापुरकर

विकसित भारत उस नागरिक-उन्मुख दृष्टिकोण को उभारता है, जिसे 'या तो/या' जैसी बेकार की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत का जैसा कद है, उस हिसाब से बहुत सी विरोधाभासी बातें सच भी हैं और उतनी ही महत्त्वपूर्ण भी। जैसे हमारी शानदार विश्व रैंकिंग पर जीत का दावा करने का अधिकार, सच्चाई यह है कि वे समग्र विकास के लिए मान्य हैं, प्रति व्यक्ति की तरक्की के लिए नहीं, और यह अनिवार्यता कि बड़ी संख्या में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के साथ-साथ सतत विकास के लिए तैयार रहने का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

इसमें रोशनी की जो किरण दिखती है वह यह कि भारत को अपने सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी क्षमता का सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। यह हमें इस बात को याद दिलाता है कि आर्थिक तरक्की की यात्रा में हमारी जनसंख्या कोई बोझ नहीं है, बल्कि इस सफर में हमारे लोग बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हें भी इस विकास यात्रा में साथ चलना और नेतृत्व करना चाहिए।

प्रतिस्पर्धी दुनिया में आर्थिक रैंकिंग वास्तव में वैश्विक निवेश का बड़ा हिस्सा हासिल करने का अच्छा पैमाना है, लेकिन यहां कोई विरोधाभास नहीं है। रणनीतिक गुरु केनिचि ओहमाए की मानें तो अपने प्रतिस्पर्धी को हराना कोई बड़ी रणनीतिक जीत नहीं मानी जाती, बल्कि ग्राहकों को गुणवत्तापरक सेवाएं देना और प्रतिस्पर्धा की जंग से बचकर आगे बढ़ जाना ही सही मायने में अच्छी रणनीति या जीत होती है। इसलिए यदि हम इस रणनीति पर चलते हुए हर वर्ष थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हुए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो बाकी चीजें अपने आप दुरुस्त होती चली जाएंगी। दुनिया हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी और सत्ता समीकरण कहीं अधिक संतुलित होंगे।

इस प्रकार के दृष्टिकोण और उच्च स्तरीय रणनीति ऐसी चीजें हैं, जिन्हें लागू करने से ही परिणाम हासिल हो सकते हैं। लेकिन, यह दृष्टि पत्र 'शुरुआत अच्छी तो आधा काम हो गया समझो' वाली कहावत को सच साबित करता है। यह सफलता के लिए एक ही रास्ते पर चलने वाले दृष्टिकोण को मानने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है और सभी लोगों को एक ही सपने को पूरा करने के लिए एकजुट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जब विजन स्टेटमेंट ने किसी देश की सोच को बदलकर रख दिया। इसका एक उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहे, जिनके सुधारों के दृष्टिकोण और समावेशी विकास की अवधारणा ने देशवासियों के खुद के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा था, 'हम विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें गरीबों और वंचित लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे, ताकि वे भी इस सफर में भागीदार बन सकें।' आज जो चीज पहले से भिन्न है, वह यह कि विकसित भारत अपनी संघर्ष यात्रा में विशेष रणनीति के रूप में कमजोर वर्गों के लिए नए अवसर उपलब्ध नहीं कर रहा है। यह लोगों की क्षमता विकास कर उन्हें सक्षम बनाने की पेशकश कर रहा है, ताकि गरीब तबके को आर्थिक विकास के लिए जरूरी सभी अवसर उपलब्ध हो सकें।

अच्छी बात यह है कि यह विकसित भारत के अतीत के नारों की तुलना में कहीं अधिक ठोस है और सफलता की तस्वीर वास्तुशिल्प के चित्रण से कहीं अधिक स्पष्ट दिखती है। दूसरी ओर, चिंताजनक खबर यह है कि हम विकसित भारत के सफर में जो शुरुआती दृष्टिकोण देख रहे हैं, उसमें सरकार आम जनता पर अधिक दबाव डालती और कहती दिख रही है कि वे विकसित भारत के लिए क्या कर सकते हैं? इस दृष्टिकोण में इस तथ्य की कमी झलक रही है कि विकसित भारत अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकता है? ऐसा लगता है कि विकसित भारत का नारा और उस दिशा में लागू होने वाली योजनाओं में देश अपने युवाओं को नई संकल्पनाओं में ढालने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्हीं पुराने, थके-हारे, खराब ढंग से काम करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के साथ उनका दोहन करना चाहता है। देशवासियों ने हमेशा से ही कम पर संतुष्ट होने के बजाय अधिक के लिए संघर्ष किया है। यही वह भावना है, जो विकसित भारत का सपना साकार कर सकती है।

आपका पक्ष

प्लास्टिक प्रदूषण : एक वैश्विक चुनौती

प्लास्टिक, आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अंधाधुंध उपयोग ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। प्लास्टिक का अपघटन सैकड़ों वर्षों में होता है और यह धरती, जल और वायु को प्रदूषित करता है। समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए दुनिया भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही हैं, उद्योग प्लास्टिक के विकल्प खोज रहे हैं और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद, प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहिए और प्लास्टिक के विकल्पों को अपनाना चाहिए। सरकारों को सख्त कानून बनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

राजूराम प्रजापत, नागौर

प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और यह धरती, जल एवं वायु को प्रदूषित करता है

ऑनलाइन सट्टा पर रोक लगाए सरकार

वर्तमान में 5 साल के बच्चे से लेकर युवा तथा प्रौढ़ तक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस युक्त स्मार्टफोन के आदी हो चुके हैं। स्मार्टफोन बेहद उपयोगी है मगर अब यह कई तरह की परेशानियों का सबब बन रहा है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर वीडियो गेम और ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त हैं। फिर टीवी और सोशल मीडिया पर बड़े-बड़ क्रिकेटर्स फिल्म स्टारों द्वारा करोड़ों रुपये कमाने के विज्ञापनों ने सभी को रातोरात करोड़पति बनने का नुस्खा बता दिया है। जिसके चलते किशोर व युवा अपना कीमती वक्त और भारी धन इस पर लुटा रहे हैं। सरकार कानून बना कर इसे रोक सकती है। इस सट्टेबाजी की लत लग जाने के कारण पढ़ने-लिखने और अन्य सकारात्मक गतिविधियों के प्रति वे लापरवाह हो गए हैं। सरकार को सभी तरह के ऑनलाइन सट्टे, गेम व अश्लील समग्री को तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए।

विभूति बुपक्या, खाचरोद

दिव्यांग बने हैं मिसाल

हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों का सशक्तीकरण और इनके लिए समान अधिकार और विकास संभावनाओं को सुनिश्चित करना भी है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार देश में दिव्यांगों की संख्या लगभग 2.68 करोड़ थी। दुनिया में कुछ दिव्यांग अद्भुत कारनामे कर दूसरों के लिए मिसाल बने हैं। वर्ष 1960 के रोम ओलिंपिक में दिव्यांग युवती विल्मा रुडोल्फ तीन स्वर्ण पदक जीत कर सबसे तेज धाविका बनी थीं। अगर देश के दिव्यांग खिलाड़ियों को पैरा ओलिंपिक के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। दिव्यांगों को शिक्षित किया जाए और उनकी क्षमता अनुसार किसी रोजगार का इंतजाम किया जाए तो स्वावलंबी होने के साथ वह अपने परिवार या आश्रितों पर बोझ नहीं बनेंगे और इनमें आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

चिंतन

संसद में गतिरोध टूटने से अब हो सकेगा कामकाज

संसद में गतिरोध का टूटना अच्छी खबर है। आज मंगलवार से दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज होगा। सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई है। 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होने के समय से गतिरोध जारी था। विपक्ष अडाणी मुद्दे, संभव मणिपुर हिंसा, संविधान पर चर्चा आदि को लेकर हंगामा कर रहा था। सोमवार को भी दिन भर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा चलता रहा। संविधान पर चर्चा को लेकर सरकार के तैयार होने के बाद ही विपक्ष ने गतिरोध खत्म कर दिया। अब मंगलवार से लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही नियमित चलने की संभावना प्रबल हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की, जहां गतिरोध खत्म करने में सफलता मिली। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐलान किया कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी तथा राज्यसभा में यह चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। इससे पहले ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार विपक्षी सांसदों से अपील कर रहे थे कि सरकार नियम के दायरे में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा था और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा था। सरकार इस शीत सत्र में एक दर्जन से अधिक विधेयक पास कराने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष के शोरगुल व हंगामे के चलते संसद चल ही नहीं पा रही थी। वक्फ बिल के मसौदे के प्रारूप तय करने के लिए बनी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की बैठकों के विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार बहिष्कार किए जाने के चलते इसकी समय सीमा बजट सत्र तक बढ़ानी पड़ी। सरकार की कोशिश रहती है कि संसद चले, पर विपक्ष के राजनीतिक व्यवधान के चलते अवरोध पैदा होता है। संसद के नहीं चलने के चलते सरकारी राजस्व का नुकसान भी होता है और विधायी कामकाज नहीं हो पाता है। देश में करीब दो दशक से परिपाटी सी बन गई है कि विपक्ष अपनी आक्रामकता से संसद को नहीं चलने देता है, सत्र दर सत्र में अवरोध कायम रहता है, इससे संसद की उत्पादकता में कमी आई है। हालांकि कुछेक सत्र अपवाद भी रहे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शीत सत्र के बाकी बचे समय में अधिक से अधिक कामकाज हो सकेगा। विपक्षी दलों ने संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 26 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान पर दो दिवसीय विशेष चर्चा का अनुरोध किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी उस दिन सभापति को ऐसा ही पत्र लिखा था। छह दिन बाद इस अनुरोध को मोदी सरकार ने स्वीकार किया है और कांग्रेस तथा 'इंडिया' गठबंधन की अन्य पार्टियों के अनुरोध के अनुसार चर्चा की तारीखों की घोषणा की गई है। दरअसल, भाजपा पर संविधान बदलने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं, जबकि भाजपा संविधान के दायरे में ही सरकार चला रही है। सरकार अपने स्तर पर भी संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को मनाने की तैयारी कर रही है। पिछले सप्ताह 25 नवंबर सोमवार से शुरु हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो सका है और पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में गतिरोध टूटना स्वागतयोग्य है। सरकार को लचीला रुख अपनाना चाहिए।

जयंती

कृष्ण प्रताप सिंह

ऐसे ही देशवासियों के 'राजेन्द्र बाबू' नहीं बने

स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने देश के इस सर्वोच्च पद पर रहते हुए अपना एक दशक से ज्यादा का जीवन राष्ट्रपति भवन में गुजारा। लेकिन इतना भर कहने से उनके व्यक्तित्व का परिचय पूरा नहीं होता। भले ही आज की तारीख में 'पहले राष्ट्रपति' के इस टैग को उन पर कुछ इस तरह चस्पां कर दिया गया है कि कई बार वह सादगी व उच्च विचार के पर्याय रहे, उनके जीवन के दूसरे प्रेरणास्पद व आदरास्पद पहलुओं को तिरोहित करने का बहाना लगने लगता है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे इन पहलुओं के प्रति बहुत सचेत रहते थे। इतने सचेत कि सत्ता के चाक्चिक्य को अपने पास फटकने नहीं देते थे। एक विश्लेषक के शब्द उधार लेकर कहें तो उनका अनासक्ति का भाव वहां भगवान राम के भाई भरत की याद दिलाता था, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास अपने 'रामचरित मानस' में लिख गए हैं : तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चम्पक बागा। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता, संविधान सभा व कांग्रेस के अध्यक्ष और पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री के तौर पर जो महनीय भूमिकाएं निभाईं, अपनी अप्रतिम सादगी से गांधीवादी मूल्यों को अगली पीढ़ियों की प्रेरणा बनाए रखने के जैसे बहुविध जतन किए और राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद जैसा निर्लिप्त जीवन जिया, वह भी श्री, समृद्धि व ऐश्वर्य के प्रति उनकी अनासक्ति का ही परिचायक है। विडम्बना यह कि आज की तारीख में उनकी जयंती (जिसे अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है) और पुण्यतिथि पर भी उनकी इन भूमिकाओं की सम्यक चर्चा नहीं की जाती। इसकी चर्चा भी नहीं ही की जाती कि वे इतने प्रतिभाशाली थे कि एक परीक्षा में उनके परीक्षक को मजबूर होकर उनकी उत्तर पुस्तिका पर लिखना पड़ा था कि इग्जामिनी इज बेटर दैन इग्जामिनर। यानी परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा मेधावी है। युवावस्था में जब वे स्वतंत्रता संघर्ष की ओर अग्रसर होने की सोच रहे थे, उनका परिवार कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा था। इस कारण वे धर्मसंकट में फंस गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि परिवार की मुश्किलें आसान करने में लगें या खुद को स्वतंत्रता संघर्ष में झोंके। झोंके तो मुश्किलों से परेशान परिजनों का जानें क्या हाल हो जाये। 1905 में ऐसी ही मुश्किलों के कारण उन्हें इंडियन सोसाइटी से जुड़ने के गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर उनसे हाथ जोड़ लेने पड़े थे। बाद में एक दिन उन्होंने अपना यह धर्मसंकट महात्मा गांधी के समक्ष रखा तो उन्होंने छूटते ही उनसे कहा, 'तुम्हारा परिवार देश से अलग तो नहीं है। तुम यह समझकर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ो कि तुम्हारा परिवार ही नहीं सारा देश मुश्किलों में फंसा है और इस लड़ाई में जो हाल सारे देश का होगा, वही तुम्हारे परिवार का भी हो जायेगा।' यह सुनकर उनका समाधान होते देर नहीं लगी और उस दिन के बाद उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। जैसा कि पहले कह आए हैं, उन्होंने न सिर्फ एक से अधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला बल्कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे। इस सबका जितना श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिला और संविधान निर्माण के श्रेय में से बड़ा हिस्सा बाबासाहब आम्बेडकर के खाते में चला गया (जो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे) तो भी वे नींव की ईंट बनकर खुश रहे। स्वतंत्रता संघर्ष में तो उन्होंने एक से बढ़कर एक कष्ट सहे ही स्वतंत्रता के बाद 1960 के गणतंत्र दिवस से ऐन पहले उनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया तो उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने पर गणतंत्र दिवस के जश्न में अपनी भागीदारी को प्राथमिकता दी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके और जवाहरलाल नेहरू के मतभेद कई बार सार्वजनिक हुए। सोमनाथ मन्दिर के उद्घाटन के मामले में भी, हिन्दू कोड बिल के मामले में भी, राजनीति में धर्म की भूमिका और भारतीय मानस को लेकर दृष्टिकोण के मामले में भी। लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी मतभेद को व्यक्तिगत कटुता तक नहीं पहुंचने दिया। जब शीत युद्ध के दौर में 13 जुलाई, 1955 को नेहरू तत्कालीन सोवियत संघ और यूरोपीय देशों की यात्रा से वापस लौटे, तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपने पद का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका बड़ी करने की नेहरू की कोशिशों पर राजेन्द्र बाबू ने अपनी प्रसन्नता जताने के लिए यह तरीका चुना था।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

विश्लेषण

अभिषेक सूर्यश

पंच परिवर्तन से राष्ट्र का जागरण

> अनेक वर्षों के राष्ट्रीय प्रयासों के बाद भारत में आज यह वातावरण बना है कि हमें अपने राष्ट्र को विश्व में श्रेष्ठ बनाना है। परन्तु कोई राष्ट्र विश्व में कैसा और किस भूमिका में होगा, ये वहां के समाज पर निर्भर करता है कि उसका व्यवहार कैसा है। इस हेतु भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन को गति देने एवं समाज में अनुशासन देशभक्ति व विजिगीषु की भावना का विस्तार करने के लिए संघ ने समाज से पांच परिवर्तन (सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, स्वत्व के भाव का जागरण, पर्यावरण व नागरिक कर्तव्य) का आह्वान किया है, जो सामाजिक व संवैधानिक दायित्वों के उद्देश्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपने स्थापना वर्ष 1925 से अनवरत कार्य करते हुए अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अपने शैशव काल से ही संघर्ष करता हुआ संघ विपरीत परिस्थितियों में और भी निखरता चला गया। व्यक्ति निर्माण की इस अभिनव कार्य पद्धति ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व कर सकने वाले हजारों कार्यकर्ता निर्माण किये जो सामाजिक चेतना जागृत करते हुए स्वाभिमानी, संस्कार युक्त तथा शक्ति संपन्न सामाजिक रचना के लिए चलायमान संगठनों का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार अनथक और अनवरत रूप से राष्ट्र की आराधना करते हुए संघ विशाल वट वृक्ष की भांति विश्व के कई देशों में हिंदू समाज के संगठन हेतु प्रयत्नशील है। अनेक वर्षों के राष्ट्रीय प्रयासों के बाद भारत में आज यह वातावरण बना है कि हमें अपने राष्ट्र को विश्व में श्रेष्ठ बनाना है। परन्तु कोई राष्ट्र विश्व में कैसा और किस भूमिका में होगा, ये वहां के समाज पर निर्भर करता है कि उसका व्यवहार कैसा है। इस हेतु भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन को गति देने एवं समाज में अनुशासन देशभक्ति व विजिगीषु की भावना का विस्तार करने के लिए संघ ने समाज से पांच परिवर्तन का आह्वान किया है, जो सामाजिक एवं संवैधानिक दायित्वों के उद्देश्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्रथम सामाजिक समरसता; जिसका पर्याय है अपनी जाति वर्ग और संप्रदाय से भिन्न लोगों के प्रति सहज सम्मानजनक और भेदभाव रहित जातिगत ऊंच-नीच जैसे सभी भेदों को भुलाकर एकात्मता का भाव जागृत कर एकात्म समरस हिंदू समाज का निर्माण करना समाहित है। सामाजिक समरसता हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए एक आवश्यक शर्त है, जिसके लिए अनेकानेक प्रयास हमारे पूर्वजों तथा ऋषि परंपरा ने किए हैं। 1966 में कर्नाटक के उडुपी में धर्म सभा को संबोधित करते हुए चारों पीठों के शंकराचार्यों ने एक स्वर में घोषणा की 'हिंदवः सहोदरः सर्वे, ना हिंदू पतितो भवेत।' अर्थात सभी हिंदू भिन्न-भिन्न गर्भ से जाये भाई हैं और कोई हिंदू पतित अथवा दलित नहीं है। जातिगत भेद कभी सनातन परंपरा में नहीं रहे। गत सहस्त्र वर्षों में जब हमारा राष्ट्र विदेशियों के आक्रमण का शिकार बना तब एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि हमारे राष्ट्र की जिस फूट ने विदेशी आक्रांताओं को सहायता प्रदान की उसके मूल में यह जाति भेद थे।

अस्पृश्यता; रोग की जड़ जनसामान्य के इस विश्वास में निहित है कि यह धर्म का अंग है। और इसका उल्लंघन महापाप होगा, यह विकृत धारणा ही शताब्दियों से अनेक समाज सुधारकों एवं धर्मधुरंधरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी जनसामान्य के मन में आज भी घर किए बैठी है। विभाजनकारी शक्तियों के षड्यंत्र को समझकर जातिवाद के नैरेटिव के जाल में ना फंसते हुए हम अपने पड़ोस, सहकर्मी तथा समाज के पिछड़ों को साथ लेकर संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम, के विचार को आत्मसात कर आगे बढ़ें।

पर्यावरण ; हमारी संस्कृति में प्रकृति पूजन को प्रकृति के संरक्षण के तौर पर मान्यता है। भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि, वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय सम्बन्ध जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है। नदी को माता स्वरूप

माना गया है। ग्रह-नक्षत्र, पहाड़ और वायु देव स्वरूप माने गए हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्यां, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम सभी इसके पुत्र हैं। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति इस प्रकार की कृतज्ञ भावना का विस्तार प्रत्येक जनमानस के हृदय में होना ही पर्यावरण संरक्षण की गारंटी है। प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपना घर हरित घर, जैविक खेती, जैव सुरक्षा, और पशुपालन की प्रतिबद्धता ही मनुष्य जाति को भी इनके गंभीर परिणामों से बचा सकती है।

कुटुंब प्रबोधन; समृद्ध भारत की सबसे छोटी इकाई है परिवार, जो सांस्कृतिक विरासत के कारण पाश्चात्य देशों में हमेशा से शोध का विषय रही है। व्यक्ति के संस्कार सभ्य समाज के निर्माण की कसौटी है। जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी कहें तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, और इसके लिए हमारे संस्कारों की पहली पाठशाला हमारा परिवार है। जो पारिवारिक रिश्तों की समझ तथा करणीय-अकरणीय का बोध कराकर व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों हेतु प्रेरित करती है। इससे ज्ञात होता है कि कौटुम्बिक व्यवस्था व्यक्ति एवं समाज के मध्य एक सेतु का कार्य करती है।

स्व का बोध; भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविता की कुछ पंक्तियों को यहां उद्धृत करना उचित होगा कि पंद्रह अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकि है रावी की शपथ न पूरी है। यह पंक्तियां हमें बार-बार स्व का बोध करने हेतु प्रेरित करती है और यह स्मरण कराती है कि स्वाधीनता से स्व-तंत्र की यात्रा अभी अधूरी है। स्व अर्थात स्वयं का तंत्र लागू करना, इसके कुछ प्रयास नवीन संसद भवन का निर्माण, दंड संहिता का न्याय संहिता के रूप में संसोधन एवं राम लला की पुनः भव्य प्राण प्रतिष्ठा भारतीय स्वत्व के जागरण के प्रमुख बिंदु हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वभाव होता है। जैसे अमेरिका का स्वभाव व्यापार है, जर्मनी का स्वभाव सामरिकता है, इस प्रकार भारत का स्वभाव धर्म है और हम उद्घोष करते हैं यतो धर्मस्य ततो जयः, यह भारतीयता है। सर्वे भवंतु सुखिनः यह भारत का विचार है, इसकी स्थापना और अध्यात्म का संदेश ही भारत का दर्शन है जो समस्त विश्व के लिए मंगलकारी है। स्व का विस्मरण आत्मविश्वास का विस्मरण है। और स्वदेशी का स्मरण अर्थात विश्वास का प्रगटीकरण है। यह स्व के भाव का जागरण ही था जिसने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए जन-जन को प्रेरित किया। अतः हम अपने विचार, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खानपान पर गर्वित होते हुए उन्हें व्यवहार में लाएं, संगीत कला, योग व लघु उद्योगों का संवर्धन हमारा विचार बने। स्वत्व के भाव का जागरण जब प्रत्येक भारतीय के हृदय में होगा तब ही भारत का भाग्योदय संभव है।

नागरिक कर्तव्य; ऋग्वेद का कथन है वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः अर्थात हम जागृत रहते हुए राष्ट्र के हित में कार्य करें। राम-कृष्ण, हनुमान, गीता, बुद्ध, महावीर सम्राट विक्रमादित्य, अशोक, शिवाजी, गुरुगोविंद और नेताजी सुभाष इत्यादि भारतीय लोकजीवन के पथ प्रदर्शक हैं संविधान की मूल रचना में इन्हें जोड़ने के पीछे यही सोच थी कि भारत की विकास यात्रा इन्हीं के प्रेरणास्पद जीवन प्रसंगों व मूल्यों के आलोक में निर्धारित की जानी चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का भान होना एक अनुशासित नागरिक के लक्षण है। संवैधानिक नियमों का पालन, राष्ट्रीय मान बिंदुओं पर आघात का प्रतिकार करना, देव-देवालय तथा संस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे चिंतन और अभ्यास के विषय हैं, यह भारतीय स्वाभिमान की जागरण का समय है।

(लेखक संस्कृतिविद् हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

भगवान के चरणों में अर्पित करना ही ज्ञान

संकलित

दर्शन

सर्व सामर्थ्य होते हुए भी अहंशून्य होकर स्वयं को भगवान के चरणों अर्पित कर देना ही ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता है। भगवान के परम भक्त बालिपुत्र अंगद ने रावण की सभा में अपना एक पैर रोपकर अपने मुष्टिप्रहार से रावण के दसों मुकुटों को सिर से गिरा दिया था, वहीं चार मुकुटों को बीच में उछालकर भगवान के पास भेज दिया था। लंका से लौटकर आए अंगद से जब भगवान श्रीराम ने पूछा कि तुमने ये मुकुट कहां और कैसे प्राप्त किए, तब अंगद ने धर्म और ईश्वर से विमुख व्यक्ति की तात्विक व्याख्या की है। अंगद विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु! ये चार मुकुट नहीं, राजनीति के चार पद हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति व्यवहार करते हुए भी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। रावण आपसे और धर्म से विमुख हो चुका है, इसलिए राजनीति के चारों चरणों (साम, दाम, दंड और भेद) का दुरुपयोग कर रहा था, इस कारण मुकुट के रूप में ये चारों उसको छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। रावण ने शेष छह मुकुट जो सिर पर धारण कर रखे हैं, वे साधक के जीवन में रहने वाली षड्संपत्ति (शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान) हैं। चूंकि रावण उनका भी दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए ये षड्संपत्ति न रहकर विकार बनकर रावण के सिर पर शासन कर रहे हैं, जो उसके विनाश के कारण बनेंगे। मेरे प्रभु! गुण तो केवल वे ही हैं, जिन्हें आपने स्वीकारा है। शेष सब अवगुण ही हैं। गुणों का योग जब तक भगवान से नहीं होगा, तब तक व्यक्ति उसका उपयोग और कहां करेगा?

मन को कभी भी निराश न होने दें

संकलित

प्रेरणा

सुबह होते ही, एक भिखारी सेठजी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया, सेठजी बाहर आए पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठजी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगीः अरे! क्या कर दिया आपने चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया। दौड़ो-दौड़ो और उसे वापिस लेकर आओ। सेठजी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोक कर कहाः भाई मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वही पर खड़े सेठजी के एक मित्र ने उससे पूछाः मित्र! जब आपको पता चल गया था कि ये गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठजी ने मुस्कुराते हुए कहाः मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो! मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास। इसी लिए कहां गया है, मन प्रसन्न तो आप प्रसन्न। प्रसन्न मन हमारे शरीर पर काफी प्रभाव डालता है। प्रसन्न मन से किए गए कार्य में सफलता की संभावना अधिक होती है।

अंतर्मन

आज की पाती

शादियों में दिखावा गरीबों के लिए मुसीबत

हमारे देश मे लोगो मे दिखावे की भावना बहुत बढ़ गई है। लगभग हर त्योहार, सामाजिक और धार्मिक समारोहो मे भी दिखावा किया जा रहा है। यह दिखावा हमारा आर्थिक नुकसान ही नही करवाता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी भंग करता है, खास तौर पर उनके लिए यह दिखावा मुसीबत बनता है जो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करते है। त्योहारो के साथ-साथ अब शादियो का मौसम भी शुरू हो गया है। हमारे देश मे शादी समारोह मे भी फिजूलखर्ची लोक दिखावे के लिए होने लगी है। लोक दिखावे के लिए लोग अपने पैर चादर से बाहर भी पसार देते है। इसके कारण अनेक समस्याएं, गरीबो के सामने पैदा होती है। दिखावे की बढ़ती परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। -विनय कुमार साहू

करंट अफेयर

कनाडा के मीडिया ने किया ओपनएआई पर मुकदमा

कनाडा के पांच सबसे प्रमुख समाचार मीडिया संस्थानों ने पिछले सप्ताह कॉपीराइट उल्लंघन के लिए 'चैटजीपीटी' की निर्माता कंपनी 'ओपनएआई' के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें अरबों डॉलर के हर्जाने की मांग की गई। यह मुकदमा इस वर्ष की शुरुआत में चैटजीपीटी के निर्माता के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका की अन्य मीडिया कंपनियों द्वारा दायर किए गए इसी प्रकार के मामलों के बाद सामने आया है। इन सभी मुकदमों के मूल में यह दावा है कि ओपनएआई ने विभिन्न मीडिया वेबसाइट से बड़ी मात्रा में वेब 'स्क्रैपिंग' की है। मुकदमे में बिना अनुमति के सामग्री की नकल करने का आरोप शामिल है। साथ ही कहा गया है कि कंपनी मूल रचनाकारों को मुआवजा दिए बिना इससे लाभ कमा रही है। वेब स्क्रैपिंग का आशय डेटा निष्कर्षण से है, जिसका उपयोग वेबसाइट से डेटा निकालने के लिए किया जाता है। ओपनएआई ने अभी तक कनाडाई मुकदमे का औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया है, लेकिन जोर देकर कहा है कि अपने चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए समाचार सामग्री का उपयोग करना कॉपीराइट कानून के तहत 'उचित व्यवहार' है, और यह किसी तरह का उल्लंघन नहीं है।

ऑफ बीट

सोशल मीडिया को अपने लिए कैसे उपयोगी बनाएं

हम सभी जानते है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आपके लिए बुरा माना जाता है। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग अवसाद और एफओएमओ (कुछ छूटने के डर) से जुड़ा है। यहां तक कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से संबंधित कंपनी मेटा का आंतरिक शोध डेटा भी इससे सहमत है। हालांकि, पिछले दशक में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन के ताने-बाने में रच-बस गया है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। युवा विशेष रूप से असुरक्षित है। 80 प्रतिशत युवा वयस्क प्रतिदिन सोशल मीडिया का उपयोग करते है, और इस पर प्रतिदिन लगभग तीन घंटे बिताते हैं। कई लोगों के लिए सोशल मीडिया 'स्क्रॉल' करना जागने के बाद उनका पहला काम और सोने से पहले का आखिरी काम है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया लोगों को दोस्तों और परिवार से जुड़ने में भी मदद कर सकता है। यह कम अहमियत रखने वाले या कलंकित पहचान वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सच है, सोशल मीडिया उन्हें समान अन्य लोगों का समुदाय ढूंढने में मदद कर सकता है, जो दूर रह सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे लिए केवल यही समाधान है कि सोशल मीडिया को छोड़ दें? क्या हमारे लिए यह सीखना संभव है कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग चतुराई के साथ करें।

X ट्रेंड f

नड्डा जी को जन्मदिन की बधाई

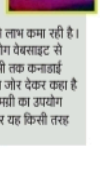

मैंने पार्टी में नड्डा जी के उल्लेखनीय योगदान को करीब से देखा है। उन्होंने हर संगठनात्मक, विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाया है। वह एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के प्रयासों में सबसे आगे हैं। उन्हें जन्मदिन की बधाई। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

राजनीति में हर व्यक्ति दुखी

राजनीति 'असंतुष्ट आत्माओं का सागर' है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। जीवन समझौतों, बाध्यताओं, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है। कोई व्यक्ति तब खत्म नहीं होता जब तक हार नहीं मान लेता है। -नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

मेक इन इंडिया दिखावा

यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक मेक इन इंडिया के शुरू होने के दस साल बाद भी भारत का विनिर्माण लगभग स्थिर है और हमारा निर्यात लड़खड़ा रहा है। सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है 'मेक इन इंडिया'। -जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

ट्रंप की धमकी स्पष्ट नहीं

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी के मायने अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी यह देखना बाकी है कि अमेरिकी कानून इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देता है या नहीं। -डी सुब्बाराव, पूर्व आरबीआई गवर्नर

अपने विचार

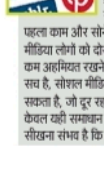

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते है।

सम्पादकीय

सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा, निष्कर्षों को अमल में लाने के ठोस उपाय

भुवनेश्वर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री का शामिल होना इस सम्मेलन की महत्ता को रेखांकित करता है। इसकी पुष्टि इस सम्मेलन में आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों के अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर गहन चर्चा से भी होती है। इस सम्मेलन में तीन दिनों तक विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के निष्कर्षों को अमल में लाने के ठोस उपाय करने से ही आंतरिक सुरक्षा को बल मिलेगा। वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई मोर्चों पर गंभीर चुनौतियां खड़ी होती हुई दिख रही हैं।

एक ऐसे समय जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर है तब हर स्तर पर कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर न केवल जोर दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे आम लोगों का सुरक्षा परिदृश्य के प्रति भरोसा और अधिक बढ़े। यह अच्छा है कि इस सम्मेलन में साइबर अपराधों पर भी गंभीर चर्चा की गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि साइबर अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साइबर अपराधी जिस तरह संगठित होकर काम करने लगे हैं, वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसियां साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं। यह ठीक है कि साइबर अपराधों के प्रति लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अपराधियों के दुस्साहस का दमन भी करना होगा। अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को एक ओर साइबर अपराधियों पर लगाम लगानी होगी और दूसरी ओर साइबर सुरक्षा के तंत्र को और अधिक मजबूत भी बनाना होगा, क्योंकि साइबर सुरक्षा में सेंधमारी भी एक बड़ी समस्या बन रही है। इस समस्या से निपटना इसलिए कठिन है, क्योंकि अक्सर यह सेंधमारी विदेश में बैठे साइबर अपराधियों की ओर से की जाती है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में पाकिस्तान प्रेरित और प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के जिन उपायों पर चर्चा हुई होगी, उनका असर जम्मू-कश्मीर में देखने को अवश्य मिलेगा। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां की स्थितियां आतंकी और जिहादी तत्वों को बल प्रदान करने वाली हैं। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन उसे पूरे तौर पर पस्त करने की आवश्यकता है ताकि नक्सली संगठन स्वयं को फिर से संगठित कर सिर न उठा सकें। यह संतोषजनक है कि नए आपराधिक कानूनों पर अमल शुरू हो गया है और इस पर सम्मेलन में चर्चा भी हुई, लेकिन बात तब बनेगी जब आम आदमी को इन कानूनों का सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा।

अमेरिकी मूल्यों से लबरेज़ परोकार, बेहतरीन टीम के साथ व्हाइट हाउस में आ रहे हैं ट्रंप....!

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर सारी दुनियाँ की नज़रे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जाकर पद संभालने पर लगी हुई है,क्योंकि उनके चुने जाने भर से ही इज़राइल हमास का 60 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर के स्थान पर ब्रिक्स करेंसी का विचार,बांग्लादेश चीन पाकिस्तान पर नकेल कसने की बातों सहित अनेक निर्णयों पर एक्शन रिएक्शन की संभावना का बाजार गर्म हो गया है तो दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन के लिए,की जा रही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे, मूल भारतवंशियों की झोली में आई है,जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रंप की बेहतरीन टीम में अभी तक शामिल साथी भारत को एक सहयोगी के रूप में देखते हैं, इसलिए बांग्लादेश के इस्कॉन पीठाधीश की गिरफ्तारी, जमानत रद्द कर जेल भेजने तथा अन्यों की गिरफ्तारी व भारत बांग्लादेश संबंधों की खराबी के एक्शन पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है तो वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर के स्थान पर ब्रिक्स करेंसी लाने के विचार पर भी रिएक्शन आ गया है,शनिवार दिनांक 30 नवंबर 2024 को देर शाम ट्रंप का बयान आया कि भारत सहित 9 देशों को खुली चेतावनी देकर कहा ऐसा हुआ तो 100 पेर्सेंट टैरिफ लगाकर अमेरिकी बाजार उन देशों के लिए बंद कर देंगे, सहित अन्य मुद्दों पर पूरी दुनियाँ की नज़रें लगी हुई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से,इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,अमेरिकी मूल्यों से लबरेज परोकार बेहतरीन टीम के साथ पद संभालने व्हाइट हाउस में आ रहे हैं ट्रंप...ट्रंप प्रशासन में भारतवंशियों का दबदबा दिखने की संभावना?

साथियों बात अगर हम ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस आने व भारतवंशियों के ट्रंप प्रशासन में दबदबा दिखने की संभावना की करें तो, अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। वे शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के उच्च पदों से लेकर देश की राजनीति में भी अहम पदों तक पहुंच रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आगामी प्रशासन के लिए अब तक कई भारतवंशियों को नामित कर चुके हैं। जबकि ट्रंप के पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार जानी मूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय रिपब्लिकन नेता के दूसरे कार्यकाल के केंद्र में होगा।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर पद के लिए नामित किया। पटेल ट्रंप के प्रशासन में कानून और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए चुना है। साथ ही, तुलसी गबार्ड और जय भट्टाचार्य को भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं। उषा वेंस ट्रंप प्रशासन की नई सेकंड लेडी बनेंगी।अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संघीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर पद के लिए अपने निकट सहयोगी एवं विश्वासपात्र काश पटेल को नामित किया। यह सेलेक्शन ट्रंप के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही ट्रंप ने अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रतिशोध की इच्छा जताई है। ऐसे में इस पद के लिए पटेल का चयन मायने रखता है।काश पटेल की नियुक्ति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही। पटेल अमेरिका में कानून व्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करेंगे।44 वर्षीय पटेल 2017 में तत्कालीन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम कुछ हफ्तों में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम कर चुके हैं।पेशे से वकील पटेल का संबंध गुजरात में वडोदरा से रहा है। पटेल भारत में अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर दिए बयान की वजह से भी चर्चा में रहे थे।निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए चुना है। बिजनेसमैन रामास्वामी का काम सरकार को सलाह देना होगा। भारतवंशी रामास्वामी करोड़पति शख्स हैं और एक दवा कंपनी के फाउंडर भी हैं।वें राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने ट्रंप का समर्थन करने का फैसला किया था।उनके माता-पिता केरल से अमेरिका चले गए थेसिनसिनाटी, ओहियो में जन्मे और पले-बढ़े, भारतीय मूल के बिजनेसमैन राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी थे। डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व सदस्य तुलसी गबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (डीएनआई) के रूप में सेवाएं देंगी। गबार्ड चार बार सांसद रह चुकी हैं। वह 2020 में वह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थीं। गबार्ड के पास पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में तीन बार तैनाती का अनुभव है। वह हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थीं।ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के टॉप हेल्थ रिसर्च एवं वित्त पोषण संस्थानों में से एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) के निदेशक के रूप में चुना है। इसके साथ ही भट्टाचार्य, ट्रंप द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। डॉ. भट्टाचार्य रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर राष्ट्र के मेडिकल रिसर्च की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे भारतीय अमेरिकी वकील उषा चिलुकुरी वेंस उस समय चर्चा में आईं, जब उनके पति जे डी वेंस को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया। ट्रंप-वेंस की जीत के साथ, 38 साल की उषा अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली हैं। इस भूमिका में उषा पहली भारतीय-अमेरिकी होंगी। उषा, ओहियो के सीनेटर जे डी वेंस (39) के साथ खड़ी थीं, जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद समर्थकों को संबोधित किया

साथियों बात अगर हम भारत बांग्लादेश तनाव व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में अमेरिकी प्रभाव की करें तो,हाल के दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरों और सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के राजनयिक रिश्तों में कड़वाहट साफ दिख रही है।इस मामले को लेकर बांग्लादेश और भारत, दोनों एक दूसरे के खिलाफ़ टिप्पणी कर चुके हैं।दोनों जगह एक दूसरे के खिलाफ़ अभियान और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। ताज़ा घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ प्रमुख लोगों और विश्लेषकों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या सरकार अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं को आंतरिक और कूटनीतिक तौर पर ठीक तरह से संभाल पाने में पूर्ण सक्षम है?ऐसे में अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि,अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया है,यह समय बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर खतरे की तरह है।लेकिन ट्रंप अब आ रहे हैं,उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकारों में शीर्ष प्राथमिकता थी।अमेरिका और भारत के बीच ऐसा सहयोग देखने को मिलेगा, जो अभी तककभी भी नहीं देखने को मिला था। साथियों बात अगर हम ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स करेंसी लाने पर विचार के रिएक्शन की करें तो,भारत समेत 9 देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी,ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने हैंडल पर लिखा,डॉलर से दूर होने की ब्रिक्स देशों की कोशिश में हम मूकदर्शक बने रहें।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके लिए कुछ लोगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। तब न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाने तथा सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करेंगे, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी, जहां यह सकारात्मकता सभी संवाद और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। शुभ समय। घर में अतिथियों का आगमन होगा।

वृष
धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कुबुद्धि हावी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। मित्रों से संबंध सुधरेंगे।

मिथुन
व्यय होगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। अज्ञात भय रहेगा।

कर्क
दूसरों के कार्य में दखल न दें। बड़ों की सलाह मानें। लाभ होगा। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। मानसिक बेचैनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। धैर्य रखें। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।

सिंह
कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शत्रु पस्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे। निवेश शुभ रहेगा।

कन्या
घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। व्यापार में वृद्धि होगी।

तुला
लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। बेवजह कहासुनी हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यापार ठीक चलेगा। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा।

वृश्चिक
प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बेवजह कहासुनी हो सकती है। कानूनी अड़चन दूर होगी। व्यापार में वृद्धि होगी।

धनु
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी सहयोग करेंगे। शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी।

मकर
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग परेशानी का कारण रह सकता है।

कुंभ
निवेश शुभ रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी अपने के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है।

मीन
शत्रु पस्त होंगे। सुख के साधन जुटेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। लंबे समय से रुके कार्य सहज रूप से पूर्ण होंगे। कार्य की प्रशंसा होगी। दुश्मनों से दूरी बनाए रखें।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार मित्रों,आज शख्सियत कॉलम में पहली बार ईश्वर के पास चले जाने वाली शख्सियत का परिचय आप तक पहुँचा रहा हूं,,मेरी ये लेखनी उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा ही दिया हुआ नाम है गजेंद्र का गज्जू दी ग्रेट। तस्वीर में सांप को अपने गले मे लिपटाए हुए चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास कोई ग्रेट ही रख सकता है। डब्ल्यू आर आर सी टीम का सुपर डुपर हंसमुख,मिलनसार, बड़ों को हमेशा सम्मान देने वाला और छोटो से प्यार करने वाला छोटे भाई समान गजेंद्र सैनी उर्फ गज्जू (रजत सैनी) सांसारिक दुनिया को छोड़कर प्रभु के श्रीचरणों में चला गया। मन काफी व्यथित है, इस शख्स के लिए । कहीं भी सांप बिच्छू, गोहरा व जंगली जीव निकलने पर एक आवाज में दौड़ने वाले के कदम थम गए हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। गजेंद्र की शख्सियत व व्यक्तित्व दिखावे से बहुत दूर ओरिजनल व सादगीपूर्ण रहा। बहुत कुछ है गज्जू दी ग्रेट के लिए उसकी शख्सियत भी अजीबोगरीब ही थी। ऐसी कौनसी आंखे हैं जो सजल ना हो। गंभीर बीमारी से योद्धा की तरह लड़ता हुआ जिंदगी की जंग हार गया। ईश्वर गज्जू की आत्मा को शांति दे। हर इंसान की मदद को तत्पर व आत्मबोध से तैयार इस शख्स की कमी हमेशा खलेगी। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआए करती है।

रूपक शर्मा

स्व.गज्जू दी ग्रेट

आज का इतिहास

प्रमुख घटनाएँ

- 1790 – लार्ड कार्नवालिस ने आपराधिक मामलों में न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीन कर अपने हाथ में कर ली और सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया।
- 1796 – बाजी राव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे।
- 1829 – वायसराय लार्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगायी।
- 1824 – अंग्रेज़ों ने मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगा कर फिर कित्तूर का किला घेर लिया।
- 1828 – एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति चुने गए।
- 1829 – वायसराय लॉर्ड विलियम बैंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगायी।
- 1860 – मारगाओ निवासी अगस्टिनो लोउरेंको ने पेरिस से रसायन शा में डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। संभवत: वे प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने विदेश से अपनी डाक्टरेट की डिग्री पूरी की थी।
- 1910 – फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री जॉर्जेज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैम्प का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन।
- 1912 – तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेग्रो ने युद्धविराम समझौता किया।
- 1943 – द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और तुर्की के राष्ट्रपति इस्मत इनोनु द्वितीय काईरो सम्मेलन में मिले।
- 1948 – पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी जहाज को ले जा रहे जहाज कियांग्या में विस्फोट होने से 1,100 लोगों की मौत हुई।
- 1959 – भारत और नेपाल ने गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 1967 – भारत का पहला रॉकेट रोहिणी आर एच 75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया।
- 1967 – इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो नजरबंद किये गए।
- 1971 – भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ।
- 1972 – होन्डुरान के सेना जनरल ओस्वाल्डो लोपेज अरेलानो ने राष्ट्रपति रमोन क्रूज का तख्ता पलट किया।
- 1974 – एक हालैंड (डच) यात्री विमान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी 191 यात्रियों की मौत हो गई।
- 1975 – लाओस गणराज्य घोषित।
- 1977 – जीन बेडेल बोकासा ने स्वयं को मध्य अफ्रीकी साम्राज्य का सम्राट घोषित किया।
- 1980 – पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फ्रांसिसको सांकाल्नरो की लिस्बन में विमान दुर्घटना में मौत हो गई।
- 1984 – भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैली गैस लीक होने से कम से कम 3000 लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए।
- 1989 – रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा की।
- 1994 – ताइवान में पहला स्वतंत्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न।
- 1999 – विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चार्ली ली बर्ड का निधन,
- 1999 – चेचेन्या के छापामारों ने 250 रूसी सैनिकों को मार गिराया।
- 2000 – विसेंट फॉक्स मैक्सिको के नये राष्ट्रपति निर्वाचित
- 2000 – आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकार्ड बनाया।
- 2001 – गाजा पर इस्रायल के हमले में यासर अराफात के हेलीकॉप्टर नष्ट।
- 2002 – यूएनडीपी ने भारत समेत सात उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता के अध्ययन के लिए 2 करोड़ 60 लाख डालर जारी किया।
- 2004 – पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय में मोनिका की अर्जी खारिज।
- 2004 – ईराक में पुलिस थानों पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत।
- 2004 – भारत और पाकिस्तान 40 वर्षों के बाद मुनाबाव और खोखरापार के बीच रेल संपर्क फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुए।
- 2008 – मुंबई में हुई 26 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

विशेष आलेख

रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देगी-ओएनओएस

सुनील कुमार महला

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोधकर्ताओं के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना यानी कि ओएनओएस(वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम) को मंजूरी प्रदान की है। वास्तव में, इस योजना को उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा और यह केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए एक सुविधा के रूप में काम करेगा।इसकी खास बात यह है कि यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है तथा यह 1 जनवरी, 2025 से संचालित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के लिए तीन वर्षों (वर्ष 2025 से 2027 तक) के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यदि हम इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य एक ही प्लेटफॉर्म पर 13,000 ई- शोध-पत्रिकाओं तक समान पहुंच प्रदान करना है। ओएनओएस योजना केवल प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी रहने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी वैश्विक स्तर पर सृजित हो रहे ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जर्मनी और उरुग्वे सरकारों ने अनुसंधान सामग्री तक समान राष्ट्रीय पहुंच की शुरुआत की थी। वास्तव में, इस पहल से भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इको सिस्टम को मजबूती मिलेगी, जिससे सरकारी प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान सुविधाओं में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध-पत्रों और पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुँच भी हासिल हो सकेगी। इस योजना से छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच तो हो ही सकेगी, साथ ही इससे शैक्षिक परिदृश्य में भी आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि यह योजना देश में शोध- उन्मुख संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के प्रयासों की पूरक है। जैसा कि ऊपर बता चुका हूं कि इस उपाय में 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-पत्रिकाओं तक पहुँच शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक स्वतंत्र अंतर- विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफिलबनेट), पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से इन संसाधनों तक पहुँच का समन्वय करेगा।इस योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत 6,300 से अधिक संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों (॥श्वडु) को एक केंद्रीय एजेंसी, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (कुह्नस्न्नुख़्नह्वश्ल्ल) केंद्र, गांधीनगर द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ह्रक्रस्न) पहल का पूरक होगा। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि एएनआरएफ स्थापना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ह्रक्रस्न) अधिनियम, 2023 के तहत भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ह्रक्रस्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति (हश्वक्क) की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इस योजना से सभी विषयों में अंत:विषयक शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं तक पहुंचेगा, जिससे शोध के अवसरों में शहरी-ग्रामीण अंतर को कम किया जा सकेगा। योजना का एकीकृत डिजिटल पोर्टल लाभार्थियों के लिए उपयोग में आसानी सुनिश्चित करते हुए पहुंच को आसान बनाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम वर्ष 2047 तक भारत के आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक अनुसंधान तक पहुंच को सक्षम करके, ओएनओएस अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की भागीदारी में सुधार करेगा और प्रभावशाली अनुसंधान परिणामों को आगे बढ़ाएगा। वास्तव में, हमारे देश में इस योजना यानी कि ओएनओएस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को शीर्ष शोधकर्ताओं की पत्रिकाओं तक विस्तारित पहुंच हासिल हो सकेगी, जिनमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं यह संस्थाओं में दोहरावपूर्ण सदस्यता को समाप्त करने के साथ ही अतिव्यापी लागत को कम करेगा और वित्त का कुशल उपयोग भी इससे सुनिश्चित हो सकेगा। इससे समझौता वार्ता भी सुदृढ़ होगी, जिससे 13,000 पत्रिकाओं के लिए लागत 4,000 करोड़ से घटकर 1,800 करोड़ रह जाएगी। इतना ही नहीं यह योजना उपयोग डेटा जर्नल पहुंच को ट्रैक करने, योजना में सुधार करने और निष्क्रिय संस्थानों के बीच बेहतर संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करने में भी सहायक सिद्ध होगी। अंत में कहना चाहूंगा कि इससे देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को मजबूती मिलेगी। कहना गलत नहीं होगा कि

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 3 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

इस चिंता के मायने

देश में जनसंख्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से बड़ा बयान दिया है, जो सोचनीय है। जनसंख्या में आ रही गिरावट को उन्होंने चिंता का विषय बताया। भागवत ने कहा किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर अगर 2.1 फीसद से नीचे चली जाती है तो वह अपने आप नष्ट हो जाता है। नागपुर के कठाले कुल सम्मेलन में कहा देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 के आस-पास तय की गई थी, जो कहती है जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 फीसद से नीचे नहीं होनी चाहिए। दो से तीन बच्चे होने चाहिए, क्योंकि समाज को जीवित रहना है। हाल ही में आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या में 7.8 फीसद की कमी आई है। संघ प्रमुख का बयान इससे जोड़ा जा सकता है। वास्तव में देश में प्रजनन दर में लगातार

गिरावट आ रही है। 1950 में जनसंख्या वृद्धि दर 6.2 फीसद थी, जो घटते हुए 2.2 फीसद पर जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है, सत्तर वर्षों में हमारी आबादी में एक अरब का इजाफा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश भारत वर्तमान में आबादी के अनुसार पहला हो चुका है। बावजूद इसके कि 2011 के बाद से आधिकारिक तौर पर जनगणना नहीं हुई है। लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है, देश के सभी धार्मिक समुदायों में प्रजनन दर कम होती जा रही है। इसका कारण सामाजिक-आर्थिक अधिक है, जिसके चलते दंपति कम बच्चे पैदा करने का निर्णय स्वयं ले रहे हैं। लंबे अरसे से सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर व्यापक प्रचार किया है। अब जबकि आम जनता छोटे परिवार के लाभ को जीवन का हिस्सा बना चुकी है। अचानक राजनीतिक व अन्य लाभों के चक्कर में जनसंख्या वृद्धि को लेकर नया भ्रम फैलाया जा रहा है। बेतहाशा बढ़ती मंहगाई और रोजगार की कमी से त्रस्त जनता बड़े परिवार का पालन करने सक्षम नहीं है। उसे तीन बच्चों के पालन के लिए बरगलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जनसंख्या दर में गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं आ रही है। दुनिया के तमाम विकसित व विकासशील देशों की यह विकराल समस्या बन गई है। जहां लोग सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं बल्कि वैश्विक व पर्यावरणीय बदलावों के चलते भी बच्चे जनने को राजी नहीं हैं। हमारे यहां आम जन इतनी दूरदर्शी या विचारशील भले ही नहीं है, मगर वह किसी की बयानबाजी में आकर जनसंख्या वृद्धि को राजी भी नहीं होने वाली।

कुछ ठोस करना होगा

डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से पैदा खतरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चिंता व्यक्त करना वाकई हम सभी को सोचने पर विवश करती है। भुवनेश्वर में तीन दिवसीय 59वें अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी सम्मेलन के समापन में प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब खतरों से निपटने के लिए पुलिस महकमे को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई इन सब धत् कर्म से निपटने के लिए बेहतरीन हथियार है और इन तकनीक का इस्तेमाल कर हम चुनौतियों से निपट सकते हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध को लेकर अपना मंतव्य दिया है। हालांकि बार-बार इस ओर ध्यान दिलाने और तमाम उपायों के बावजूद ऐसे अपराधों की बाढ़ सी है। दरअसल, हमारे देश में अब अमूमन हर किसी के पास मोबाइल है। साथ ही

ज्यादातर जनता पैसों का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती है। स्वाभाविक है, साइबर अपराधियों के लिए शिकार की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब पुलिस के सामने ऐसे मामलों की बाढ़ सी है। और यह बड़ी चुनौती के रूप में है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के पहले नौ महीनों के दौरान साइबर धोखाधड़ी के कारण भारत को 11,333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा से यह भी पता चला है कि अकेले 2024 में साइबर धोखाधड़ी की लगभग 12 लाख शिकायतें दर्ज की गईं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 45 प्रतिशत मामले कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आए हैं। आए दिन मीडिया में डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध के जरिये लाखों की ठगी के मामले सुर्खियों में रहते हैं। जाहिर है लोगों में जागरूकता का अभाव है। यहां तक कि पुलिस भी इनसे लड़ने में खासी दिक्कतों का सामना करती है। इस नाते सबसे पहले साइबर पुलिसिंग को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना होगा। वहीं जनता को लगातार जागरूक और सजग करने के लिए काम करना होगा। गाढ़ी कमाई का इस तरह लुट जाना वाकई तकलीफ की बात है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मोर्चे पर काम होगा।

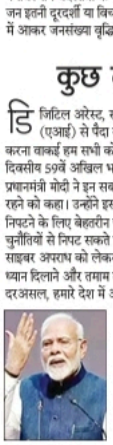

जलवायु परिवर्तन/अमित बैजनाथ गर्ग

आधी आबादी झेल रहीं दुश्वारियां

संयुक्त राष्ट्र की ओर से हाल ही में महिला आधारित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2050 तक जलवायु परिवर्तन के चलते 158 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां गरीबी की ओर जा सकती हैं। वहीं 236 मिलियन से अधिक महिलाओं और लड़कियों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में हर साल 130 मिलियन लड़कियों को शिक्षा के मानवाधिकार से वंचित रखा जाता है और जलवायु संबंधी संकट इस दिक्कत को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसे मुश्किल समय में लड़कियों की जल्दी शादी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उन्हें घर की जरूरतों में मदद करने के लिए सबसे पहले स्कूल से निकाला जाता है। जलवायु संकट, क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग और अथाह वायु प्रदूषण ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है, उनका सबसे अधिक सामना महिलाओं को ही करना पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते पूरी दुनिया में मां की कोख में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हवा में बिखरे हैवी मेटल्स मां की सांस के जरिए अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायु प्रदूषण नवजातों के दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए घातक है। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने पर पॉल्यूशन प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच रहा है। इससे शिशु के दिमाग और फेफड़े सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण महिला स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचआईवी-एड्स, मलेरिया और टीबी के लिए हर साल बड़े वैश्विक कोष का निवेश किया जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिहाज से ऐसा नहीं है। असल में जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर गहरे तक पड़ने वाला प्रभाव संवेदनशील मुद्दा है। जागरूकता फैलाने, शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच प्रदान करने, आर्थिक अवसर प्रदान करने और प्रभावी नीतियों को लागू करके हम आधी आबादी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

अनमोल वचन

आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममत्व रखनेवाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता

-भगवान महावीर

नतीजे के निहितार्थ

उप्र चुनाव परिणाम

अवधेश कुमार

उत्तर प्रदेश उपचुनाव का महत्व इसलिए है क्योंकि लोक सभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा धक्का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही लगा था। अगर इन राज्यों के परिणाम भाजपा की अपेक्षाओं के अनुरूप आए होते तो वह लोक सभा में अकेले बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती। सपा ने अपने जीवन का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कांग्रेस भी एक से छह सीट तक पहुंच गई। लोक सभा चुनाव के बाद प्रदेश में हुए इस पहले चुनाव में भाजपा और सपा दोनों के जन समर्थन का परीक्षण होना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वैचारिक वाकद्वंद्व में भी यह संकेत मिलना था कि किनके वायदों और नारों को आम जनता ज्यादा स्वीकार कर रही है।

परिणाम सामने है और इसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देशव्यापी उपचुनावों का एक विश्लेषण यह है कि जहां जिस पार्टी का शासन था वहां उसे सफलता मिली है। यहां एक मौलिक अंतर लोक सभा चुनाव की विभाजक रेखा का है। उप्र उप चुनाव में परिणाम पलट गया है तो तत्काल इसके इसे इसी रूप में देखना होगा। नौ विधानसभा क्षेत्र में अगर छह भाजपा और एक उसकी सहयोगी रालोद जीती, सपा दो पर सिमट गई तो इसका अर्थ क्या है? पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें सपा ने चार जीती थी और उसकी सहयोगी रालोद एक। इस तरह उसके पास पांच विधानसभा सीटें थीं। इस बार उसकी उम्मीदें ज्यादा सीटें जीतने की थी।

मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में 60 फीसद से ज्यादा मुसलमान है। 31 वर्ष बाद वहां भाजपा की विजय वर्तमान परिस्थितियों में असाधारण है। इसी तरह अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट है। यहां 33 वर्ष बाद भाजपा जीती। देश भर के नामी मुस्लिम चेहरे, संगठन, संस्थाएं जिन दो लोगों को मुसलमान और इस्लाम का दुश्मन साबित कर रहे हैं, वे हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ। वहां कुंदरकी में मुसलमान टीवी कैमरे पर आकर कह रहे थे कि हम भाजपा के उम्मीदवार को वोट देंगे तो सहसा सपा या आईएनडीआईए घटकों या उनके समर्थकों के लिए विश्वास करना मुश्किल था।

भाजपा ने गाजियाबाद, फूलपुर, खैर और मझवां भी जीती तो सहयोगी रालोद मीरापुर फिर से जीत गई। प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी का पीडीए या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण कहां गया? करहल और सीसामऊ में उसे जीत मिली, लेकिन करहल यादव परिवार का गढ़ माना जाता है और वहां भी सपा को केवल 14 हजार वोट से विजय मिली जबकि तेज प्रताप यादव को परिवार का चेहरा बनाकर उतारा गया और अनुजेश प्रताप को बली का बकरा कहा गया। पांच स्थानों पर भाजपा की विजय बड़े अंतर से हुई। दूसरी ओर करहल के अलावा सीसामऊ में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भाजपा के सुरेश अवस्थी को केवल 8,564

मतों से हराया। तो इसे पप्रदेश के मतदाताओं की सोच और व्यवहार में लोक सभा चुनाव के विपरीत आए परिवर्तन का द्योतक क्यों न माना जाए? ऐसा परिणाम क्यों आया? लोक सभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की विदाई और 2027 में भाजपा सरकार की पराजय की घोषणा करने वाले अखिलेशजी और उनकी पार्टी ने चुनाव परिणाम को सत्ता के भयानक दुरुपयोग और धांधली की परिणति बताया है।

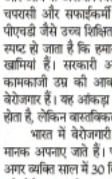

मतदान के दिन सपा ने ऐसे वीडियो जारी किए जिनसे लगता था कि पुलिस प्रशासन मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोक रही है, धमका रही है, कानूनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भाजपा के लिए काम कर रही है। अखिलेश जी ने पत्रकार वार्ता की और इसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लेकर सात पुलिसकर्मियों को निलंबित और ड्यूटी मुक्त कर दिया। आरोपों को अभी तक साबित नहीं किया जा सका। पुलिस पर पत्थरबाजी के दृश्य भी लोगों ने देखे और पुरुष व महिला मतदाताओं से बहस भी सुनी। जब भी चुनाव में हिंसा की संभावना दिखती है या होती है तो पुलिस प्रशासन सख्त व्यवहार करता है क्योंकि उसका दायित्व कानून और व्यवस्था बनाए रख चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन की है। कार्रवाई के शिकार पुलिस वालों को लेकर प्रशासन ने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप भूमिका निभाने की बात कही। बावजूद सपा को समस्या है तो उसे चुनाव आयोग के अलावा न्यायालय में अवश्य जाना चाहिए। उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में बहुमत मतदाता हो तो पुलिस प्रशासन उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं कर सकता।

डिजिटल जमाने में सबके पास मोबाइल है और कोई घटना छिप नहीं सकती। इसीलिए लगातार सपा के आरोपों और हमलों का सामना करने वाली पुलिस कहीं उनके विरुद्ध हो तब भी ऐसा एकपक्षीय परिणाम बगैर मतदाताओं के समर्थन के संभव नहीं। उपचुनाव में विजय के बाद उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर प्रिंट मीडिया के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दाएं और बाएं उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खड़े हैं, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री को मिठाई खिला रहे हैं। यह तस्वीर भी प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी कुछ सकारात्मक संदेश दे रही थी।

लोक सभा चुनाव परिणाम के बाद कुछ समय तक मुख्यमंत्री अवश्य थोड़े दबाव में दिखे किंतु उनका तेवर लौटा और उन्होंने उपचुनाव की घोषणा के पहले ही धुआंधार प्रचार आरंभ किया। आगरा में उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाते हुए 'बटेंगे तो कटेंगे' की बात की और चूंकि धरातल पर वातावरण था इसलिए लोगों तक इसकी भावना पहुंची। प्रधानमंत्री ने 'बटेंगे तो दुश्मन महफिल सजाएंगे' और फिर 'एक रहेंगे तो नेक रहेंगे' का नारा दिया और यह दो विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही नहीं, चारों ओर फैल गया। ध्यान रखिए, इन उपचुनावों को भाजपा ने प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा, योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मथुरा और काशी के पुनरुद्धार की खुलकर बात की, वक्फ संशोधन का समर्थन किया। इस आधार पर चुनाव परिणाम को देखें तो तत्काल निष्कर्ष यही है कि सपा की 2014,2017, 2019 और 2022 की लगातार पराजय का दौर जारी है। सपा इस सच्चाई को समझ कर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाए तथा वैसे चेहरों को आगे लाए जो इसे समझ कर बोलें व काम करें तभी उसकी पुनर्वापसी संभव होगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

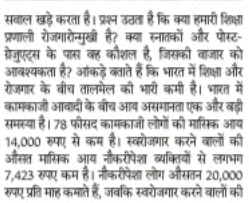

> लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कुछ समय तक मुख्यमंत्री अवश्य थोड़े दबाव में दिखे किंतु उनका तेवर लौटा और उन्होंने उपचुनाव की घोषणा के पहले ही धुआंधार प्रचार आरंभ किया। आगरा में उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाते हुए 'बटेंगे तो कटेंगे' की बात की और चूंकि धरातल पर वातावरण था इसलिए लोगों तक इसकी भावना पहुंची। प्रधानमंत्री ने 'बटेंगे तो दुश्मन महफिल सजाएंगे' और फिर 'एक रहेंगे तो नेक रहेंगे' का नारा दिया

सहकारी क्षेत्र में 2030 तक साढ़े पांच करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की क्षमता

- भारत के सहकारी क्षेत्र में 2030 तक प्रत्यक्ष रूप से 5.5 करोड़ नौकरियां और 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है
- सहकारी क्षेत्र पर एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सहकारी तंत्र वैश्विक स्तर पर 30 लाख सहकारी समितियों में से करीब 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

साहसी बनें, जोखिम लें। अपने दिल की सुनें। डर की बजाय साहस को चुनें। अपने आप को अन्वेषण करने और विकसित होने का मौका दें-यही सबसे कीमती है।

हर्ष गोयनका, उद्योगपति@hvgoenka

गहराता जा रहा संकट

बेरोजगारी **नृपेन्द्र अभिषेक नृप**

बेरोजगारी भारत के सबसे जटिल और गंभीर मुद्दों में से एक है, जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह समस्या केवल नौकरी की कमी तक सीमित नहीं है; यह रोजगार की गुणवत्ता, स्थायित्व और आय के असमान वितरण से भी जुड़ी है। जब क्लर्क, चपरासी और सफाईकर्मी जैसे पदों के लिए एमए और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षित लोग आवेदन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी रोजगार व्यवस्था में बुनियादी खामियां हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कामकाजी उम्र की आबादी में केवल 3 फीसद लोग बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा पहली नजर में आशावादी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है।

भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए दो प्रमुख मानक अपनाए जाते हैं। पहला सामान्य स्थिति है जिसमें अगर व्यक्ति साल में 30 दिन से अधिक काम करता है, तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। दूसरा साप्ताहिक स्थिति, जिसमें अगर व्यक्ति सप्ताह में एक घंटे भी काम करता है, तो उसे बेरोजगार की सूची से बाहर कर दिया जाता है। भारत में यह परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल वास्तविक बेरोजगारी को छुपाती है, बल्कि नीतियों को प्रभावी बनाने में भी बाधा उत्पन्न करती है। यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इससे असली बेरोजगारों की गिनती ही नहीं होती। विकसित देशों की परिभाषा इससे बहुत अलग है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 15 से 74 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, जो सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा है, और जिसने पिछले चार सप्ताह में काम की तलाश की है या दो सप्ताह के भीतर काम शुरू करने के लिए उपलब्ध है, वह बेरोजगार की श्रेणी में आता है। शिक्षा को हमेशा रोजगार का माध्यम माना जाता है, लेकिन भारत में यह धारणा बदलती हुई नजर आ रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, बिना पढ़े-लिखे लोगों में 59.6 फीसद रोजगार में हैं। इसके विपरीत, स्नातक और उससे अधिक शिक्षित लोगों में रोजगार दर केवल 57.5 फीसद है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट-2024 के आंकड़े दर्शाते हैं कि कम पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर केवल 3.2 फीसद है, जबकि उच्च शिक्षित वर्ग में यह दर 28.7 फीसद तक पहुंच जाती है। यह विरोधाभास कई

सवाल खड़े करता है। प्रश्न उठता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगारोन्मुखी है? क्या स्नातकों और पोस्ट-ग्रेजुएट्स के पास वह कौशल है, जिसकी बाजार को आवश्यकता है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में शिक्षा और रोजगार के बीच तालमेल की भारी कमी है। भारत में कामकाजी आबादी के बीच आय असमानता एक और बड़ी समस्या है। 78 फीसद कामकाजी लोगों की मासिक आय 14,000 रुपए से कम है। स्वरोजगार करने वालों की औसत मासिक आय नौकरीपेशा व्यक्तियों से लगभग 7,423 रुपए कम है। नौकरीपेशा लोग औसतन 20,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं, जबकि स्वरोजगार करने वालों की आय इससे बहुत पीछे है। साथ ही भारत में बड़ी संख्या में लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जिनमें वे न्यूनतम वेतन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या असंगठित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। आय की इस असमानता का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति को भी बाधित करता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का स्वरूप और इसके कारण अलग-अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात करें तो यहां ज्यादातर लोग कृषि और असंगठित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। मौसमी रोजगार, कम आय, और स्थिरता की कमी यहां की प्रमुख समस्याएं हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी में बेरोजगारी दर अधिक है क्योंकि प्रतिस्पर्धा तीव्र है और नौकरी के अवसर सीमित हैं। उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में अधिक है। भारत में महिलाओं की रोजगार भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। सामाजिक बंधन, शिक्षा की कमी, और परिवार की प्राथमिकताओं के कारण महिलाएं कामकाजी क्षेत्र से दूर हो जाती हैं।

इससे पहले कि बेरोजगारी और मुश्किलें पैदा करें इसका समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि पहला, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा को व्यावसायिक और कौशल विकास के साथ जोड़ा जाए। दूसरा, स्वरोजगार को बढ़ाया जाए। स्वरोजगार के लिए आसान ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएं। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने इसपर काम किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि लोगो में लोन का अभी भी भय है जिसे दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है। तीसरा, असंगठित क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। चौथा, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई जाए। बेरोजगारी का संकट केवल आंकड़ों की समस्या नहीं है, यह करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। इस दिशा में ईमानदारी और सतत प्रयास ही भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बना सकते हैं।

ब्रह्मचर्य **ओशो**

जब दो शरीर के बीच आकर्षण होता है तो काम; जब दो मनों के बीच आकर्षण होता है तो प्रेम--जिसे हम प्रेम कहते हैं; जब दो आत्माओं के बीच आकर्षण होता है तब प्रार्थना; और जब दो बिल्कुल खो

जाते हैं, दो ही नहीं रह जाते, तब इसे, जिसको दादू प्रेम कहते हैं; जिसको जीसस ने प्रेम कहा है। वह आखिरी ऊंचाई है। वे सीढ़ियां तुम्हारे भीतर हैं। तुम पहली ही सीढ़ी पर खड़े रह जाओ तो कोई और जिम्मेवार नहीं है। दूसरी सीढ़ी पास ही थी, लेकिन कोई अड़चन होनी चाहिए। कोई गहरी बाधा होनी चाहिए। इतने लोग चूक जाते हैं कि करीब-करीब ऐसा लगता है, चूकना स्वाभाविक है। और इतने कम लोग उपलब्ध हो पाते हैं कि ऐसा लगता है, पाना अपवाद है, नियम नहीं। कोई बुद्ध, कोई चैतन्य, कोई दादू, कोई नानक-कभी करोड़ों लोगों में एक। बाधा है: मरने का डर। क्योंकि जितनी ऊंचाई पर तुम जाते हो, उतना ही तुम्हारा अहंकार क्षीण होने लगता है। जितनी ऊंचाई होगी, उतने ही तुम कम हो जाओगे। यह डर है। जितनी नीचाई होगी, उतने ही तुम रहोगे। ठीक जमीन पर पड़े रहो तो पत्थर की चट्टान की तरह तुम होओगे। स्वभावतः ऊपर उठना हो तो पत्थर की चट्टानें ऊपर नहीं उठतीं; सुगंध उठती है, अग्नि की शिखा उठती है, भाप उठती है। विरल हो जाना पड़ता है। स्वयं को खोना पड़ता है। कामवासना में कोई खोता नहीं अपने को। कामवासना में तुम रहते हो। तुम दूसरे का उपयोग कर लेते हो। तुम मिटते नहीं, वस्तुतः तुम दूसरे को मिटाने की चेष्टा करते हो। इसीलिए तो पति-पत्नियों में इतनी कलह है सारे संसार में पूरे मनुष्य-जाति के इतिहास में। हजार तरह से सोचा गया है कि पति-पत्नी की कलह कैसे मिटे। कोई उपाय नहीं दिखता। कलह मिट नहीं सकती, ऐसा लगता है। जब तक मनुष्य ऊपर न उठना सीखे, कलह नहीं मिट सकती। कलह यही है कि पत्नी पति को मिटाने की चेष्टा कर रही है, पति पत्नी को मिटाने की चेष्टा कर रहा है। एक गहन संघर्ष है, जो चाहे उन्हें ज्ञात भी न हो। पति कोशिश कर रहा है कि मैं सब कुछ हूं, तू मेरी परिधि है। पत्नी भी यही कोशिश कर रही है कि मैं केंद्र हूं, तुम परिधि हो। दोनों के अहंकार अपने को बचाने की चेष्टा में संलग्न हैं। कहीं दूसरा मिटा न दे। इसके पहले कि दूसरा मिटाए, मैं उसे मिटा दूं; यही सुरक्षा का उपाय मालूम पड़ता है। इसलिए कामवासना प्रेम की तो बड़ी दूर की खबर है, हिंसा की ज्यादा।

रीडर्स मेल

ट्रंप के थोथे दावे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर का विकल्प अपनाने पर 100 फीसद सीमा शुल्क लगाने की धमकी वैश्विक व्यापार और कूटनीति के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है। यह कदम न केवल बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। भारत, जो ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य और अमेरिकी बाजार का महत्त्वपूर्ण भागीदार है, इस स्थिति में संतुलन साधने की कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। भारत को अपनी आर्थिक स्वायत्तता मजबूत करते हुए डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार प्रणाली और पारदर्शी वित्तीय ढांचे का विकास करना होगा। साथ ही, ब्रिक्स सहयोग को सशक्त बनाते हुए अमेरिकी व्यापारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह समय है कि भारत सतर्कता, दूरदर्शिता और कूटनीतिक कुशलता का प्रदर्शन करे।

आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी, मप्र

चिंता की बात

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गौतम अदाणी पर 265 मिलियन डॉलर के रिश्वत योजना के आरोप के बाद, कई प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों ने लगभग सभी अदाणी समूह की कंपनियों की रेटिंग को नकारात्मक कर दिया है। यह घटनाक्रम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समूह को दिए गए अरबों रुपए के ऋणों को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। ऐसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन वित्तीय संस्थानों ने रिजर्व बैंक के निर्धारित ऋण दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया है? वर्तमान परिस्थिति में सभी उधारदाताओं को साथ बैठकर इन परिसंपत्तियों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करना होगा और सख्त कदम उठाने होंगे। साथ ही उन्हें वितरित किए गए सभी धन के उपयोग पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी।

चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

महिलाएं मजबूत हुई या कमजोर

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिलाओं को लक्षित करने वाली हाल की नकद हस्तांतरण योजनाओं की व्यवहार्यता जांच के दायरे में आ गई है। भले ही ये पहल मतदाता मतदान को बढ़ा सकती है, लेकिन क्या वे वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाती हैं या वे केवल राजनीतिक चाल है? इसी तरह, क्या ये योजनाएं अनजाने में श्रम आपूर्ति को कम कर सकती हैं, जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा? भविष्य में कल्याण नीति पर विचार करते समय, क्या हमें तत्काल राजनीतिक अधिग्रहण से पहले दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देनी चाहिए?

अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार

केजरीवाल की नौटंकी

केजरीवाल द्वारा इंडिया गठबंधन को धता बताकर दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा सिर्फइंडिया गठबंधन को दबाव में लेने की रणनीति है। क्योंकि लोक सभा चुनाव के समय जेल में रहते केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से यही नाटक रचवाया था। वस्तुतः केजरीवाल की हकीकत से आम जनता वाकिफ हो चुकी है और उनकी नौटंकी को समझने लगी है।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर, उप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 108
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी